भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1418
31 जुलाई 2024 को उत्तर देने के लिए

राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति

†1418. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश, विशेषकर विशाखापट्टनम में चल रही भू-स्थानिक मानचित्रण पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, विशेषकर विशाखापट्टनम में भू-स्थानिक मानचित्रण परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित और संवितरित की गई है और उनके कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त नीति के भाग के रूप में विशाखापट्टनम सहित आंध्र प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे उच्च-रिसोल्यूशन स्थलाकृतिक सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश में विशेषकर विशाखापट्टनम में स्थानीय रूप से निर्मित भू-स्थानिक आंकड़ों के उपयोग और एकीकरण को राष्ट्रीय भू-स्थानिक नॉलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर (जीकेआई) में बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ड़) क्या आंध्र प्रदेश विशेषकर विशाखापट्टनम में भू-स्थानिक पहलों के कार्यान्वयन में कोई विलंब अथवा चुनौतियां आ रही हैं अथवा सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार(
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केन्द्र के माध्यम से नीली अर्थव्यवस्था को सहायित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साहचर्य में संधारणीय विकास और तटीय रक्षण हेतु भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए तटरेखा प्रबंधन योजना तैयार की है।

(**ख**) राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति के तहत भू-स्थानिक मानचित्रण परियोजनाओं हेतु निधियों का राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया है।

(**ग**) **से** (**ङ**): विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीनस्थ संगठन, सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरे आंध्र प्रदेश राज्य (कृषि भूमि, आबादी और शहरी सहित सभी प्रकार की भूमि) के लगभग 52,096 वर्ग किमी क्षेत्र में पुनर्सर्वेक्षण हेतु आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर 19.12.2020 को किए हैं। ड्रोन फ्लाइंग, ऑर्थोरेक्टिफाइड इमेजरी (ओआरआई) सृजन और 52,096 वर्ग किमी क्षेत्र का लक्षण सार पूर्ण हो चुका है। सर्वे ऑफ इंडिया ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ परस्पर सहमति से लवण बेसिन (साल्ट-पैन) भूमि की मानचित्रण परियोजना प्राप्त करके उसे पूर्ण किया है। आंध्र प्रदेश में 23,160 एकड़ लवण बेसिन भूमि का ओआरआई तैयार किया गया है।

*****